

प्रेषक,

एम0 एच0 स्नान,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 19 मई, 2010

विषय:- अनुदान सं0-27 के जिला सेक्टर आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010, शासनादेश संख्या-249/XXVII(1)/2010, दिनांक 04 मई, 2010, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-1391/53-रा0यो0अ0/वि0जि0यो0/2007-08 दिनांक 27 अप्रैल, 2010 एवं पत्र सं0-1407/123-रा0यो0अ0/प्लान/2010 दिनांक 29 अप्रैल, 2010 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र सं0-नि.1805/3-4 दिनांक 14 मई, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन विभाग के अंतर्गत संचालित जिला सेक्टर योजनाओं हेतु संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार रु0 9,05,00,000/- (रु0 नौ करोड़ पांच लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण / व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किस्तों में किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनाएँ एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निर्वर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. आहरण-वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
5. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग(त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
6. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।
7. व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार विशेषकर आयोजनेतर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXVII(1)/2009, दिनांक 16 जुलाई, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः.....2

10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
 11. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
 12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
 13. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
 14. निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
 15. विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे. उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी. केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा.
 16. जिन योजनाओं में विगत वर्षों की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो इनके परिप्रेक्ष्य में सम्पन्न औपचारिकताएं पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष होगा. भारत सरकार को समय से ऑडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जायें, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो.
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान सं०-27 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 91-जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

(धनराशि रु० हजार में)			
क्र.सं.	योजना का नाम / मानक मद	मद प्रकार	वर्तमान स्वीकृति
1	9101-वन संचार साधन		
	25. लघु निर्माण कार्य	साख-सीमा	30000
	29. अनुरक्षण		20000
	योग		50000
2	9102-भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था		
	24. वृहद निर्माण	साख-सीमा	20000
	25. लघु निर्माण कार्य		8000
	26. मशीन साज सज्जा		2500
	29. अनुरक्षण		10000
	योग		40500
	कुल योग		90500

(वर्तमान स्वीकृति रु० नौ करोड़ पांच लाख मात्र)

- 3- उक्त आदेश शासनादेश सं०-1391/53-रा०या०आ०/वि०जि०यो०/2007-08 दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(एम० एच० खान)

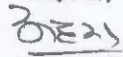
सचिव

संख्या- (1)/X-2-2010, तददिनांकत.

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.

3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल (जे).

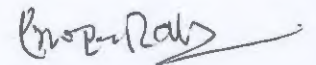
आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव

शासनादेश सं०-^{अ-143}/X-2-2010-12(28)/2006 दिनांक 19 मई, 2010 का संलग्नक-

(धनराशि रू० हजार में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम								
		वन संचार साधन			भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था					
		मानक मद			मानक मद					
		लघु निर्माण कार्य	अनुरक्षण	योग	वृहत निर्माण कार्य	लघु निर्माण कार्य	मशीन सज्जा/संयंत्र	अनुरक्षण	योग	कुल योग
1	नैनीताल	0	1285	1285	0	624	56	535	1215	2500
2	ऊधमसिंह नगर	0	300	300	1467	587	183	734	2971	3271
3	अल्मोड़ा	1501	1001	2502	1954	782	244	977	3957	6459
4	बागेश्वर	1236	824	2060	2201	880	275	1100	4456	6516
5	पिथौरागढ़	1180	787	1967	1064	425	133	532	2154	4121
6	चम्पावत	2023	1349	3372	1247	499	156	623	2525	5897
7	देहरादून	3934	2622	6556	3107	344	308	1233	4992	11548
8	टिहरी	3254	2169	5423	0	899	80	321	1300	6723
9	पौड़ी गढ़वाल	4776	3184	7960	2469	869	298	880	4516	12476
10	चमोली	2298	1532	3830	2292	917	287	1146	4642	8472
11	रूद्रप्रयाग	2529	1686	4215	1100	440	138	550	2228	6443
12	उत्तरकाशी	7269	2911	10180	1834	734	229	917	3714	13894
13	हरिद्वार	0	350	350	1265	0	113	452	1830	2180
	योग	30000	20000	50000	20000	8000	2500	10000	40500	90500

(वर्तमान स्वीकृति रू० नौ करोड़ पांच लाख मात्र)


(एम० एच० खान)
सचिव